MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Death sentence announced to seventeen Indian in UAE

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में उन सत्रह भारतीयों को, जिनको यू.ए.ई. में सजा-ए-मौत दी गई है और उसके अलावा पचास भारतीयों को उस केस में टॉर्चर किया गया है, के बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने जिस ढंग से रवैया अपनाया हुआ है, उससे उन परिवारों में बड़ा जबर्दस्त रोष है। ऐसा लग रहा है कि सरकार उस बात पर इंटरनेशनल दबाव, उस देश पर बना पाई है। यह एक इनह्यूमन एक्ट है और इसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी उन परिवारों से मिलकर, जो पॉलिसी है, वह क्लियर करनी चाहिए और उन भारतीयों को रिहा करवाने का प्रयास करना चाहिए। जिनको टॉर्चर किया गया है, उनके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर, यू.एन.ओ. में जाकर उनके कम्पेनसेशन का भी दबाव बनाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा (पंजाब) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

Problem of storage of Grains in Warehouses of FCI and possibility of its Rottening by being kept in open

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, देश में जहां एक ओर महंगाई बढ़ रही है, अगर उसी एवज में देखें तो एफ.सी.आई. की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10,37,738 मीट्रिक टन खाद्यान्न अनाज गोदामों में, पिछले छह-सात वर्षों में सड़ गया है। इनके भंडारण की कीमत लगाई गई थी। यह इतना अनाज है कि एक साल तक एक करोड़ आदमी को भर पेट खिलाया जा सकता है। इस भंडारण में 243,21,59,726 रुपए लगे हैं। मजेदार मामला है कि सड़े अनाज को हटाने के लिए 2,69,40,490 रुपए खर्च हुए हैं। पंजाब में 72 लाख टन गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। मैं यह सड़ा गेहॅं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ।

श्री उपसभापति : आप इसे नहीं दिखा सकते।

श्री प्रभात झा : सारा गेहूँ सड़ रहा है। 65 लाख टन गेहॅं पर तिरपाल नहीं है। देश भर में गेहॅं के उत्पादन का 50 फीसदी हिस्सा पंजाब और हरियाणा देता है, हम सब जानते हैं। आज यह स्थिति बन गई है कि समय नहीं है, अगर समय पर केंद्र सरकार नहीं चेती, तो बहुत नुकसान होगा। 18 फरवरी को सी. रंगराजन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुप्रबंधन के कारण महंगाई बढ़ रही है। देखिए, कितना बड़ा मजाक है कि एक तरफ लाखों टन गेहॅं भण्डारण के अभाव में, तिरपाल के अभाव में सड़ रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है और लोग भूखे मर रहे हैं। यह क्या है? शरद पवार जी खाद्य मंत्री भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं। पता नहीं सरकार ने उन्हें किस काम में लगाया हुआ है, शायद उनकी जानकारी में है कि नहीं, वे कह देते हैं कि यह सारा मामला राज्यों पर जाता है। कितना बड़ा मजाक है? क्या यह राष्ट्रीय अपराध नहीं है, क्या यह national crime नहीं कहा जाएगा कि लाखों